शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 मई 2021
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

मध्यप्रदेश के दतिया जिले के पिछड़ेपन के कारण एवं निदान

डॉ. मनीषा मिश्रा
अर्थशास्त्र
अतिथि विद्वान
कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट
इंदौर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

आर्थिक पिछड़ापन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अति गंभीर समस्या है। ये अन्य समस्याओं का कारण है। इसको समाप्त करने के लिए सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार की एक योजना 'जवाहर रोजगार योजना' 1 अप्रेल 1989 में लागू की गई । इसी 'जवाहर रोजगार योजना' के प्रभाव का शोध अध्ययन मध्य प्रदेश के दतिया जिले के दो विकास खण्ड, दतिया एवं सेंवढ़ा में (1991-97) के काल खण्ड में सम्पन्न किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र उसी पर आधारित है।

शोध पत्र का उद्देश्य

मध्यप्रदेश के दतिया जिले के विशेष संदर्भ में 'जवाहर रोजगार योजना' (शासकीय योजनाओं) को प्रभावित करने वाले कारकों को ज्ञात करना तथा विकास के लिए उपयुक्त सुझाव प्रेषित करना।

शोध क्षेत्र

दतिया जिले के दो विकास खण्ड दतिया एवं सेंवढ़ा का चयन किया गया। इन दोनों में 10-10 गाँव अध्ययन के लिये चुने गये जो निम्न प्रकार से हैं -

दतिया विकास खण्ड के गाँव

1. गोरा
2. बेटरा
3. पचोखरा
4. मलक पहाड़ी
5. डोगरपुर, बशेप, गढ़ा
6. बहरूखा
7. लेतरा
8. लिधोरा
9. अलीपुरा
10. रडुवापुर

सेंवढ़ा विकास खण्ड के गाँव

1. सहेरा
2. नीमडांडा,
3. जरा
4. मगरोल
5. भगरोल
6. हुकी
7. संजयपुरा
8. खमरोली
9. मदनपुरा
10. चिताई
11 नन्दपुर
12 महला

ग्रामों का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि द्वारा किया गया।

अध्ययन की इकाई

अध्ययन हेतु दोनों विकासखण्डों के लाभांवित परिवारों को चुना गया। जिसमें दतिया विकासखण्ड के 10 ग्रामों के कुल 181 परिवार और सेंवढ़ा विकासखण्ड के कुल 182 निर्धन परिवार चुने गये। इस प्रकार से कुल 363 निर्धन परिवार अध्ययन हेतु चुने गये। परिवारों का चयन दतिया जिले की जनगणना सूची में सूचीबद्ध निर्धन परिवारों में से किया गया।

शोध विधि

शोध हेतु निम्न शोध विधियां अपनाई गईं -

1. सर्वेक्षण पद्धति
2. संरचित अनुसूची
3. द्वितीयक समंक संकलन हेतु विविध पुस्तकालयों में अध्ययन किया
4. सांख्यिकीय निदर्शन

योजना की सीमित सफलता का मूल्यांकन

अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ, कि योजना एक सीमा तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है। इसका विवरण निम्न प्रकार से है -

1 व्यावसायिक ढांचे पर प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन में वृद्धि हुई तथा उनकी आय में वृद्धि हुई जिससे उन्होंने छोटेछोटे व्यवसाय आरंभ किये और उन्हे दैनिक नकद आय प्राप्त होती है। यह आय यद्यपि थोड़ी है, किन्तु उनकी सीमित आवश्यकताओं में यह महत्वपूर्ण योगदान करती है। लेकिन ये लाभ स्थाई नहीं था। कुछ दिनों बाद वे अपनी स्थिति को बनाये नहीं रख पाये।

2 पलायन पर प्रभाव

लाभार्थी परिवार गर्मी के मौसम में पारम्परिक रूप से लिये जाने वाले पलायन से सुरक्षित रहे, क्योंकि उन्हें योजना के तहत रोजगार प्राप्त हो गया था।

3 निर्धनता पर प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्र में अध्यामित परिवारों में गरीबी के स्तर में तुलनात्मक रूप से गिरावट दर्ज की गई। अर्थात् उनकी आर्थिक स्थिति कुछ उन्नत हुई लेकिन यह बहुत थोड़ी थी क्योंकि श्रम दिवसों की संख्या कम थी तथा पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।

4 आवास पर प्रभाव

इसकी सहायक योजना 'इंदिरा आवास योजना' के अंतर्गत उन निर्धन परिवारों को मकान बनाने के लिये धन राशि उपलब्ध कराई गई, जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि थी। किन्तु अनेक लाभार्थियों ने अत्यधिक भागदौड़ की शिकायत की।

5 कृषि उत्पादन पर प्रभाव

इस योजना में 10 लाख कुएं लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु निर्मित कराने के लिये सहायता राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे सिंचाई के कारण उनके कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई किन्तु यह वृद्धि सीमित है, क्योंकि कृषकों के पास कृषि भू क्षेत्र का आकार बहुत छोटा है।

6 रोजगार पर प्रभाव

यह बेरोजगारी उन्मूलन की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पंचायत स्तर पर परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जाता है, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इससे लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, किन्तु अशिक्षित होने के कारण लोगों को पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। अतः वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुये।

योजना की सफलता में बाधायें एवं त्रुटियां

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है, कि 'जवाहर रोजगार योजना' की सफलता सीमित रही है। इसकी पूर्ण सफलता में निम्नलिखित मुख्य बाधायें हैं -

1 ग्रामीण निर्धनों में जागरूकता के अभाव से वे अपना पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं।

2 योजना का क्षेत्रीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप न होना।

3 योजना के उचित प्रचार-प्रसार का अभाव रहा है। अतः लोग लाभ नहीं ले पाये हैं।

4 भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही के कारण पंचायत स्तर पर अधूरी योजनाओं को पूर्ण दिखाकर धनराशि हड़प ली गई तथा अनेक बार योजना

लालफीताशाही के कारण अत्यंत धीमी गति से चली।

5 पंचायत स्तर पर व्याप्त 'भाई-भतीजावाद' एवं 'जातिवाद' के कारण अनेक अपात्र हितग्राहियों का चयन हुआ एवं पात्र हितग्राही लाभ से वंचित रहे।

6 अनेक बार धनराशि का निर्धारित कार्य के लिये उपयोग न करके शादी-ब्याह जैसे कार्यों के लिये किया गया।

योजना की त्रृटियां

योजना में अनेक त्रृटियां विद्यमान पाई गई जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं -

1 ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वयन योजना की त्रृटि है, क्योंकि अधिकांश सरपंच अशिक्षित व कम योग्य थे तथा निजी सम्बंधों को भी महत्व प्रदान किया गया।

2 पंचायत सचिवों ने सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, अनेक पंचायत सचिव, पंचायत कर्मी के रूप में संविदा पर नियुक्त पाये गये। इनकी नियुक्ति में सरपंच की इच्छा निर्णायक होती है। अतः वे उनके प्रभाव में वित्तीय अनियमितताओं की अनदेखी करते रहे।

3 योजना के निरीक्षण के लिये विशेष व्यवस्था का अभाव रहा तथा प्रशासनिक अधिकारियों के पास कम समय रहा।

4 योजना के क्रियान्वयन में जनभागीदारी का अभाव रहा।

5 अनेक महिला संरपंचों के स्थान पर उनके पति दायित्व निभाते हुये पाये गये। जिन्होंने आर्थिक लाभ के लिये अनियमिततायें की।

6 योजना में श्रम दिवस बहुत कम रखे गये जबकि लोगों को अधिक कार्य दिवस हेतु रोजगार की आवश्यकता रहती है। अतः लोगों ने कम रूचि प्रदर्शित की।

7. योजना में लोगों को कोई प्रषिक्षण प्रदान नहीं किया गया, इसलिये वे स्वरोजगार स्थापित करने में असफल रहे।

शासकीय योजनाओं की सफलता हेतु सुझाव

यदि जवाहर रोजगार योजना को एक निदर्ष (सेम्पल) मानकर विचार करें, तो निम्नलिखित सुझावों द्वारा शासकीय योजनाओं की सीमित सफलता को दूर करके उन्हें पूर्ण सफल बनाया जा सकता है। इसकी सफलता हेतु मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं -

1. योजना के लागू होने के पूर्व से ही उसकी जानकारी आमजन तक पहुंचाने हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

2. जनभागीदारी की प्राप्ति हेतु ग्रामीणों में शिक्षा एवं जागरूकता का स्तर उन्नत किया जाना चाहिए ।

3. योजनाओं का स्वरूप स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए।

4. ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को तथा आम जनता को शासकीय कार्य पद्धतियों का उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

5. भाई-भतीजावाद एवं जातिवाद जैसे तत्वों पर कठोरता से नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए।

6. ग्रामीण योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीण पृष्ठभूमि के कर्मिकों को महत्व प्रदान किया जाना चाहिए।

7. भुगतान चैक से या सीधे खाते में किया जाना चाहिए।

8. स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग जनभागीदारी एवं जागरूकता उत्पन्न करने हेतु किया जाना चाहिए।

9. योजनाओं के निरीक्षण हेतु विषेष दलों का गठन किया जाना चाहिए।

10. योजनाओं की सफलता हेतु महिलाओं की जनभागीदारी पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

11. योजनाओं के उचित क्रियान्वयन पर पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जबकि असफल क्रियान्वयन पर पंचायतों को दण्डित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

इस प्रकार से स्पष्ट है कि जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने एवं ग्रामीण जीवन स्तर उन्नत करने हेतु प्रस्तावित की गई थी, किन्तु यह अपने पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाई तथा सीमित रूप से ही सफल रही। इसकी सीमित सफलता के कारण अनेक हैं, जिनमें संरचनागत त्रुटियाँ, क्रियान्वयन संबंधी त्रुटियां और परिस्थितिजन्य समस्यायें मुख्य हैं। भ्रष्टाचार तो एक मुख्य समस्या है ही। अतः इन समस्याओं का समाधान करके जवाहर रोजगार योजना या अन्य किसी भी शासकीय योजना को सफल बनाया जा सकता है ।

संदर्भ ग्रंथ

1 अग्रवाल, ए.एन.(1998), भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास एवं आयोजन, विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली

2 भारत की जनगणना (1981) मध्य प्रदेश सीरीज-।।

3 दत्त, रुद्र एवं सुंदरम केपी.एम.(1998), भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चंद एण्ड कंपनी लि.,नई दिल्ली

4 मुड़ोतिया, मनीषा (2004), दतिया जिला में जवाहर जवाहर रोजगार योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन 1991-97, अप्रकाशित शोध-प्रबंध, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

5 जिला सांख्यिकी पुस्तिका (1997), जिला दतिया

6 मध्यप्रदेश सांख्यिकी संक्षेप, 1994, भोपाल

7 योजना, दिसंबर (1998), नई दिल्ली

8 शर्मा, रामरतन (1998), भारतीय अर्थव्यवस्था, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल

9 शर्मा, टी.आर. एवं वार्ष्णेय, जे.सी.(1988), विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन, साहित्य भवन, आगरा